

प्रस्तावना

1) निः शुल्क बाजारों के तहत सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान है, सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने नागरिकों को सार्वजनिक समान प्रदान करना है ,विशेष रूप से एक समाज में कमजोर वर्गों के लिए । जबकि आमिर निजी विकल्पों की तलाश कर सकते हैं , बेहतर सेवाएँ जुटा सकते हैं , या आदि आवश्यक हो तो उन क्षेत्रों में जा सकते हैं जहाँ सार्वजनिक सामान बेहतर प्रदान किए जाते हैं , गरीबों के पास शायद ही इस तरह के विकल्प हैं (बेसले और घटक, 2004) । इस प्रकार सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान विशेष रूप से एक समाज में कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है । फिर भी , सरकारें लोकतंत्र में क्षितिज की समस्या से पीड़ित हो सकती है , जहाँ समय क्षितिज जिस पर सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ मतदाताओं तक पहुंचते हैं , चुनावी

चक्रों से अधिक लंबा सकता है । क्षितिज की समस्या से उत्पन्न मायोपिया फिर से सार्वजनिक वस्तुओं की अंडर -प्रोविजनिंग हो सकती है । इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान जो आर्थिकवस्था और समाज के लिए दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न करता है एक लोकतान्त्रिक राजनीति में शासन के प्रमुख पहलु का प्रतिनिधित्व करता है ।

- 2) जैसा देखभाल एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है , क्रमिक सरकारों ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है । हालाँकि , 2018 तक UHC एक मायावी सपना बन रहा । 2018 में भारत सरकार ने देश में सबसे कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सेवा पहुँच प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी । लाभार्थियों में 10.4 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के लगभग 50 करोड़ व्यक्ति शामिल

थे , जो भारतीय आबादी के निचले 40% हिस्से को बनाते हैं | परिवारों को क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 से वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर शामिल किया गया था | यह योजना पारिवारिक फ्लोटर के आधार पर प्रति खर्च प्रति परिवार 5 लाख रु तक की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है , जिसका अर्थ है की इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है यह योजना सार्वजनिक और सशक्त निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रदान करती है | यह पूर्व अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिनों के लिए प्रदान किया जाता है , उम्र और लिंग या परिवार का आकार पर कोई सीमा नहीं रखता है , और देश भर में पोर्टेबल है | इसमें 23 विशिष्टताओं सहित 1573 प्रक्रियाएं शामिल हैं | आयुष्मान भारत जन आरोग्य

योजना सम्पूर्ण जनसंख्या को चहुमुखी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध करने हेतु 150,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य भी रखा है ।

3) PM-JAY के साक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पर मजबूत सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं । सबसे पहले , उच्च आवृत्ति , कम लागत वाली देखभाल के लिए PM-JAY का काफी उपयोग किया जा रहा है । दावों के वितरण का उपयोग करते हुवे हम पते हैं की वितरण एक लम्बी पूंछ वाला है जो INR 10,000 -15,000 की सीमा में है । प्राप्त पूर्व- प्राधिकार के दावों की उच्चतम संख्या ऐसी प्रक्रियाओं के लिए थी जिनकी लागत इस सीमा थी । अधिक भारी प्रक्रियाओं के लिए वितरण बहुत कम दावों का संकेत देता है की वितरण सही तरह से होता है ।

4) दूसरा सामान्य चिकित्सा 2018 के बाद से इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख नैदानिक विशेषता रही है और

इसके शेयर लगातार बढ़ रहे हैं | इसके बाद सामान्य सर्जरी , प्रसूति और स्त्री रोग हैं | ये तीन श्रेणियां औसत से प्राप्त दावों के आर्थ से अधिक हिस्से को जोड़ती हैं | डायलिसिस – उच्च आवृत्ति , कम लागत वाली प्रक्रिया जो गुर्दे की कठिनाइयों वाले रोगियों के लिए जीवन रक्षक है – PM-JAY के तहत सामान्य चिकित्सा श्रेणी के दावों के एक बड़े हिस्से (30%) के लिए ज़िम्मेदार हैं

5) तीसरा कोविड-19 के कारण या मार्च – अप्रैल 2020 में Lockdown के कारन भी डायलिसिस के दावे कम नहीं हुवे, जबकि हम Lockdown के दौरान समग्र सामान्य चिकित्सा श्रेणी के तहत दावों में भारी गिरावट देख सकते हैं | इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान डायलिसिस जैसे महत्वपूर्ण , जीवन रक्षक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया गया है |